COP16 की ओर
सूचना नोट #3

जून 2024 में तैयार किया गया

वैश्विक जैव विविधता ढांचे का लक्ष्य 3

- लक्ष्य 3 क्या है?
- लक्ष्य 3 कैसे प्राप्त किया जाएगा?
- लक्ष्य 3 के प्रति प्रतिक्रियाएँ
- स्व-निर्धारित विकल्प

यह दस्तावेज़ जून 2024 में CBD COP16 के लिए कैलि, कोलंबिया में तैयारी के समर्थन के लिए तैयार किया गया था।

यह विशेष रूप से आदिवासी लोगों के लिए एक परिचयात्मक रिपोर्ट के रूप में उपयोग करने के लिए है, और इसे मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से लिखा गया है।

अधिक जानकारी के लिए: CBD@forestpeoples.org

लक्ष्य 3 क्या है?

टारगेट 3, 2030 तक भूमि, जल और महासागरों सहित प्राकृतिक दुनिया के 30% क्षेत्र के संरक्षण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है। और, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह न केवल आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों के योगदान को पहचानकर, बल्कि उनके अधिकारों को पहचानने, सम्मान करने, उनकी रक्षा करने और आदर करने की सक्रिय कोशिश करने के लिए प्रतिबद्ध है।

क्या? कम से कम 30 प्रतिशत स्थलीय और आंतरिक जल क्षेत्रों, और समुद्री और तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से जैव विविधता और पारिस्थितिकी प्रणालियों के कार्यों और सेवाओं के लिए विशेष महत्व वाले क्षेत्रों को प्रभावी रूप से संरक्षित और प्रबंधित किया जाता है ...

कब? 2030 तक

कैसे? ... पारिस्थितिक रूप से प्रतिनिधि, अच्छी तरह से जुड़े और समान रूप से शासित संरक्षित क्षेत्र प्रणालियों और अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संवर्धन उपायों (ओ. इ. सी. एम) के माध्यम से आदिवासी और पारंपरिक क्षेत्रों को पहचानना जहां उपयुक्त हो, और व्यापक परिदृश्य, समुद्र और महासागरों में एकीकृत किया जाए, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि कोई भी स्थायी उपयोग, जहां ऐसे क्षेत्रों में उपयुक्त हो, संरक्षण परिणामों के साथ पूरी तरह से संगत है ...

किसके बिना नहीं ... स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को पहचानें और उनका सम्मान करें, जिसमें उनके पारंपरिक क्षेत्र भी शामिल हैं।

आदिवासी और पारंपरिक इलाके (आई टी टी)

संरक्षित क्षेत्र (पी ए)

अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संवर्धन उपाय (ओ ई सी एम)

संरक्षण मार्ग

टारगेट 3 कैसे पूर्ण किया किया जायेगा?

संरक्षित क्षेत्र (पे. ए)

अधिकांश, बड़े पैमाने पर संवर्धन की पहल पारंपरिक रूप से संरक्षित क्षेत्रों (पी. ए) के माध्यम से की गई। पीए 'भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र होते है जिनमे विशिष्ट संवर्धन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विनियमित और प्रबंधित किया जाता है' (Article 2, CBD). इन्हें सरकारों, निजी ट्रस्ट या कंपनियों, या आदिवासी लोगों के समूहों और स्थानीय समुदायों, या इन सब के संयोजन द्वारा (उदाहरण के लिए, संयुक्त प्रबंधन) घोषित और प्रबंधित किया जा सकता है।

> जब वे बाहरी एजेंटों द्वारा बनाए जाते हैं, आदिवसी लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान किए बिना, तो पाया गया है की पे.ए इन क्षेत्रों पर कब्जा, स्वामित्व या उपयोग करने वालों के अधिकारों के बेदखली या उल्लंघन का कारण बन सकते हैं।

अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संवर्धन उपाय (ओ ई सी एम)

2010 में, सी बी डी-कोप ने एक और संवर्धन नीति अपनाई। अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संवर्धन उपाय (ओ ई सी एम): एक भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र (संरक्षित क्षेत्र से परे), जो उन तरीकों से शासित और प्रबंधित किया जाता है जो संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों और सेवाओं के साथ जैव विविधता के इन-सीटू संवर्धन के लिए सकारात्मक और निरंतर दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करते हैं और, जहां उपयुक्त हो, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक-आर्थिक और अन्य स्थानीय रूप से प्रासंगिकमूल्य।

> ओ ई सी एम को संवर्धन परिणाम दिखाना ज़रूरी है, भले ही यह उस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य नहीं हो। पीए की तरह, इन क्षेत्रों को आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों सहित कई व्यक्ति और समूह द्वारा शासित किया जा सकता है।

आदिवासी और पारंपरिक इलाके (आई टी टी)

2022 में, सी बी डी-कोप ने, जी बी एफ में संवर्धन के लिए एक और "मार्ग" को मान्यता दी: आदिवासी और पारंपरिक इलाके (आई टी टी)। यद्यपि " आदिवासी और पारंपरिक इलाके" इनकी कोई सहमत परिभाषा नहीं है, उन्हें आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा स्वामित्व, कब्जे और/या उपयोग की जाने वाली भूमि, इलाके और क्षेत्रों के रूप में समझा जाता है। टारगेट 3 के संदर्भ में, इन क्षेत्रों के प्रथागत शासन और प्रबंधन संवर्धन परिणामों में योगदान करते हैं।

> आदिवासी और पारंपरिक इलाके को मान्यता देने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें संरक्षित क्षेत्रों के रूप में भी मान्यता नहीं दी जा सकती। उन्हें ओ ई सी एम के रूप में पहचाना, मान्यता प्राप्त और रिपोर्ट (आदिवासी और पारंपरिक समुदायों के स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के साथ) किया जा सकता है, । उन्हें आदिवासी या पारंपरिक क्षेत्रों के रूप में अपनी शर्तों पर टारगेट 3 के योगदानकर्ताओं के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

क्या आपको और कुछ जानने की ज़रूरत है?

टारगेट 3 यह भी पुष्टि करता है कि 30% क्षेत्र तक पहुंचने के लिए किए गए सभी कार्यों को "आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों (जिसमें उनके पारंपरिक क्षेत्र भी शामिल हैं) के अधिकारों को पहचान कर और उनका सम्मान करके ही करना होगा।

अधिकारों को पहचानने और सम्मान करने की इस प्रतिबद्धता को ऊपर वर्णित तीन मार्गों में अपनाए गए संवर्धन कार्यों को रेखांकित करना चाहिए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आदिवासी और पारंपरिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर टारगेट 3 की पूर्ति के लिए मान्यता दी जाए और गिना जाए।

लक्ष्य 3 के प्रति प्रतिक्रियाएँ

यह महत्वपूर्ण है कि सरकारें, संरक्षण संगठन और अन्य लोग टारगेट 3 की नई भाषा को समझें और लागू करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पी ए, ओ ई सी एम और आदिवासी और पारंपरिक इलाकों को 30% संवर्धन तक पहुंचने की दिशा में गिना जाये।

जैव विविधता के संवर्धन के लिये आदिवासी और पारंपरिक इलाकों के योगदान को पे ए, या ओ इ सी एम, के रूप में पहचाने जाने या राज्य के पर्यावरणीय अधिकार क्षेत्र के अधीन किए बिना मान्यता दी जानी चाहिये।
जैव विविधता संरक्षण के लिए आदिवासी और पारंपरिक इलाकों के योगदान को प्रभावित लोगों और समुदायों को स्वीकार्य हो ऐसे तरीके से (उनके अधिकारों के लिए पूर्ण सम्मान के साथ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाना चाहिए।

हालाँकि, यदि सरकारें और अन्य लोग आदिवासी और पारंपरिक इलाकों को मान्यता दिए बिना विशुद्ध रूप से तकनीकी दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, और आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का पूरी तरह से सम्मान किए बिना पी ए की स्थापना और ओ ई सी एम को मान्यता देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना और आदिवासी और स्थानीय लोगों को इन क्षेत्रों के शासन और प्रबंधन में प्रभावी ढंग से भाग लेने की अनुमति दिए बिना, संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण होगा।

सरकारें और संरक्षण संगठन अक्सर संवर्धन और संरक्षित क्षेत्रों को बनाने के लिए धन संस्थाओं पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग वित्तपोषण प्रदान करते हैं, वे पीए या ओ ई सी एम के कार्यान्वयन और प्रबंधन में बहुत अधिक प्रभाव डाल सकते हैं।

इसलिए, उनकी जिम्मेदारी है के वे लागू मानकों का पालन करने और मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी संवर्धन पहलों से बचे. इसके विपरीत, पी ए और ओ ई सी एम अपने उद्देश्यों और दायित्वों (जैसा कि टारगेट 3 में निर्धारित किया गया है) को पूरा कर रहे है ये सुनिश्चितकरने में वे सक्रिय भूमिका निभा सकते है.

स्वनिर्धारित विकल्प

आदिवासी लोग और स्थानीय समुदाय अलग-अलग तरीकों से और अपनी शर्तों पर, टारगेट 3 के तीन मार्गों में भाग ले सकते हैं। जैसे की:

- **संरक्षित क्षेत्र (पी ए)**

जहां राष्ट्रीय कानून अनुमति देते हैं, आदिवासी लोग और स्थानीय समुदाय सरकारों और अन्य लोगों के साथ सह-प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र या आदिवासी या समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षित क्षेत्र स्थापित कर सकते हैं। इसका परिणाम ऐसे पीए हो सकते है जो पूरी तरह से आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों के स्वामित्वऔर शासित हैं, या जिनके पास सरकारी निकायों के साथ कुछ स्तर के साझा अधिकार और जिम्मेदारीहैं।

- **अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संवर्धन उपाय (ओ ई सी एम)**

Iस्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय ओईसीएम और मौजूदा संवर्धन क्षेत्रों की पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना चुन सकते हैं जिनका वे प्रबंधन और स्वामित्व करते हैं। यह मौजूदा शासन या प्रबंधन व्यवस्था को बदलने के बिना किया जा सकता है। यह चल रहे संवर्धन परिणामों का समर्थन करने के लिए संवर्धन संगठनों जैसे अन्य लोगों के साथ सहकारी समझौते स्थापित करके भी किया जा सकता है।

- **आदिवासी और पारंपरिक इलाके (आई टी टी)**

Tये क्षेत्र आदिवासी लोगों या स्थानीय समुदायों (पारंपरिक जीवन शैली पर आधारित) के क्षेत्र हैं, जहां जैव विविधता पहले से ही जीवन के तरीकों और अपने स्वयं के प्रथागत कानूनों के माध्यम से वे संवर्धन कीए जा रहे है।

लक्ष्य 3 में गिने जाने के लिए, सरकारों को आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं के अनुसार, जैव विविधता के संवर्धन के लिए आदिवासी और पारंपरिक क्षेत्रों के योगदान को पहचानना होगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह पीए और ओईसीएम ढांचे के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन जहां उपयुक्त विकल्पों पर विचार नहीं किया जाता है, इन क्षेत्रों (आई टी टी) को मान्यता देना आवश्यक विकल्प हो सकती है।

> आदिवासी और पारंपरिक लोगों और राष्ट्रीय कानून की परिस्थितियों के आधार पर, आदिवासी और पारंपरिक क्षेत्रों की मान्यता कानूनी सुरक्षा, भूमि या इलाके के पट्टे, भूमि सीमांकन आदि प्राप्त करने का अवसर हो सकते है।

यह काफी हद तक राष्ट्रीय परिस्थितियों और वर्तमान या सूत्रीकरण में राष्ट्रीय कानूनी ढांचे पर निर्भर करेगा। राष्ट्रीय नीति के माध्यम से आधिकारिक मान्यता और भूमि और जल के पट्टे प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। स्थानीय अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ शुरू में काम करना जैव विविधता संरक्षण में आदिवासी और स्थानीय समुदाय की भूमिका की मान्यता प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है, जो फिर राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और कानूनों में शामिल किया जा सकता है।